

सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के
अध्याय-2 की धारा - 4(1) ख 8

मैनुअल संख्या -8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण
जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस
बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि
क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें
जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक
जनता की पहुँच होगी।

कारपोरेशन की व्यवस्था

निदेशक मण्डल:-

निदेशक मण्डल की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं लेकिन एक तिमाही में एक बैठक होना आवश्यक होता है। कारपोरेशन की दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था प्रबन्ध निदेशक के द्वारा देखी जाती है, जोकि निदेशक मण्डल के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं अधीक्षण में कार्य करते हैं। प्रबन्ध निदेशक को कारपोरेशन के तीन पूर्ण कालिक निदेशक एवं अन्य अधिकारी सहयोग करते हैं। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल में निम्न निदेशक सम्मिलित हैं:-

1. श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. श्री आर० मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
3. डॉ० अहमद इकबाल, अपर सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
4. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
5. मेजर योगेंद्र यादव, अपर सचिव (नियोजन), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
6. श्री अनिल कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
7. श्री सी० एम० वासुदेव, म०सं० - 44, सैक्टर- 44, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा।
8. श्री बी०पी० पाण्डे, बी-4/42 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, यू०पी०।
9. श्री आलोक रावत, सी-231, वसंत विहार, फेस-1, पो०ओ०, न्यू फारेस्ट, देहरादून।
10. श्री पराग गुप्ता, साकेत लेन 1, म०सं० 13, 76/1, राजपुर रोड़, देहरादून।
11. श्री पी०सी० ध्यानी, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
12. श्री एन० के० गुप्ता, निदेशक(वित्त), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
13. श्री एम० एल० प्रसाद, निदेशक(परिचालन), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
14. श्री अजय कुमार अग्रवाल, निदेशक(परियोजना), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।

सम्प्रेक्षा समिति:-

कारपोरेशन के उत्तम वित्तीय अनुशासन के लिए कारपोरेट स्तर पर एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया गया है, समिति में कम से कम तीन सदस्य सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्तमान में सम्प्रेक्षा समिति में निम्न तीन सदस्य हैं:-

1. श्री बी०पी० पाण्डे, बी-4/42 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, यू०पी०।
2. श्री सी० एम० वासुदेव, म०सं० - 224, सैक्टर- 15- ए, नोएडा- 201301
3. श्री अनिल कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।

निदेशक मण्डल द्वारा यदि कोई प्रकरण उद्घृत किया गया हो तो सम्प्रेक्षा समिति को इसकी पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार है। समिति को पूर्ण विकल्प प्राप्त है कि वह कारपोरेशन के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करे और इस हेतु यदि आवश्यकता पड़े तो वाह्य व्यावसायिक सलाह भी प्राप्त कर सकती है। समिति समय-समय पर

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर सम्प्रेक्षकों से संवाद स्थापित कर सकती है, सम्प्रेक्षण का उद्देश्य वित्तीय विवरण को निदेशक मण्डल में जाने से पूर्व पुर्नवालीकन होता है।

सामाजिक दायित्व समिति:—

कम्पनी अधिनियम की धारा 135 (3)(अ) के अनुसार जिस कम्पनी का कुल मूल्य रू0 500 करोड़ या वार्षिक कारोबार रू0 1000 करोड़ या अधिक या किसी भी वित्तीय वर्ष में रू0 5 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया गया है ऐसी कम्पनियाँ द्वारा सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया जायेगा।

उपरोक्त के अनुक्रम में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 71वीं बैठक दिनांक 23.07.2015 में निम्नानुसार सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया।

1. श्री सी0 एम0 वासुदेव, म0सं0 – 224, सैक्टर– 15– ए, नोएडा– 201301
2. श्री अनिल कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
3. श्री आर0जे0 मलिक, अधिशासी निदेशक(मा0सं0) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।

उपरोक्त सामाजिक दायित्व समिति हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 74वीं बैठक में सामाजिक दायित्व समिति नीति का निर्धारण किया गया है जोकि **संलग्न** है।

कारपोरेशन के अंशधारक:—

कारपोरेशन के अंशधारक निदेशक मण्डल से उच्च अधिकारिक होते हैं क्योंकि अंशधारकों का धन कारपोरेशन में निवेशित होता है, क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम है इसलिए शतप्रतिशत अंश उत्तराखण्ड सरकार के पास है।

कारपोरेशन के वर्तमान अंशधारक निम्न प्रकार हैं:—

1. माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. डा0 एस0 एस0 सन्धु, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
3. श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
4. डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
5. डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव (नियोजन), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
6. श्री विनय शंकर पाण्डे, सचिव(उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
7. श्री दिलीप जावलकर, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
8. डॉ अहमद इकबाल, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
9. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव(वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
10. श्री अनिल कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
11. श्री संदिप सिंघल, प्रबन्ध निदेशक, यूजेविएन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
12. श्री विक्रम सिंह राणा, संयुक्त सचिव, (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
13. श्री अतुल कुमार सिंह, अनु सचिव, (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।

कम्पनी की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली के लिए निदेशक जवाबदेह होते हैं जबकि अंशधारकों की संगठन में उच्च पदस्थिति होती है वे कम्पनी अधिनियम 2013 के प्राविधानों के तहत निदेशकों पर नियन्त्रण रखते हैं।

क्या निदेशक मण्डल, परिषद, समिति एवं अन्य निकाय लोकार्थ हैं ? या इनकी बैठकों के निर्णय बिन्दु लोकार्थ के लिए सुगम है।

निदेशक मण्डल की बैठकों में कारपोरेशन की सभी नीतिगत प्रकरणों पर चर्चा होती है, बोर्ड बैठकों में उपस्थिति आम लोगों के लिए खुली नहीं होती।

जहां तक सम्प्रेक्षण समिति एवं अंशधारकों की बैठकों का सम्बन्ध है, इन बैठकों में अन्य लोग भागीदारी नहीं कर सकते। सम्प्रेक्षा समिति तथा अंशधारकों की बैठकों में लिए गये निर्णय आम लोगों को नहीं बताये जाते, लेकिन फिर भी कम्पनी अधिनियम में निहित यथोचित निषेध प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक दिन कम से कम दो घण्टें अंशधारकों के निर्णय बिन्दु कार्य समय के दौरान केवल अंशधारकों (सदस्यों) के निरीक्षण के लिए शुल्क जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है।

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LIMITED

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY OF UPCL

Short Title and Commencement

This policy may be called "Corporate Social Responsibility Policy of Uttarakhand Power Corporation Limited. In short this policy shall be termed as "UPCL CSR Policy".

This policy shall come in to force from the date it is approved by the Board of Directors of the Company and shall be applicable from financial year 2015-16.

Definitions

In this policy, unless the context otherwise require:

1. 'Act' means The Companies Act, 2013.
2. 'Board' means the Board of Directors of UPCL.
3. 'Company' shall mean Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL), A Government of Uttarakhand undertaking having its registered address at VCV, Gabar Singh Bhawan, Kanwali road, Dehradun .
4. 'Corporate Social Responsibility' shall mean the Corporate Social Responsibility as defined under Section 135 of the Act.
5. 'Government' shall mean Government of Uttarakhand.
6. 'Ministry' shall mean the Ministry of Corporate affairs, Government of India.
7. 'Net Profit' shall mean net profit before tax as per books of the accounts calculated as per provisions of Section 135 of the Act.
8. 2% of CSR spending shall be calculated as 2% of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years. For the purpose of first CSR reporting the net profit shall mean average of annual net profit of the preceding three financial years ending on or before 31st March, 2016.
9. Reporting will be done on annual basis starting from financial year 2015-16.
10. Words and expressions used in this policy and not defined here in but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Guiding Principle

- CSR is the process by which UPCL shall think about and evolve its relationship with the stakeholders for the common good and demonstrate its commitment in this regard by adoption of appropriate business processes and strategies.
- CSR does not intend to act as a charity or donation.
- CSR shall be a way to conduct business by UPCL in which it will visibly contribute the social good. The CSR activities will be used to integrate economic, environmental, social and other statutory objectives.

Scope

The Corporate Social Responsibility activities shall be undertaken by the Company as a project or programme or activities (either new or ongoing) excluding the activities undertaken by the Company in pursuance of normal course of business. The items that would be undertaken under CSR activities shall be as enumerated in Schedule VII of The Companies Act, 2013 as amended up to date.

CSR Committee

- CSR Committee has been constituted by Board of Directors on 23rd July'2015 as under:

| | | |
|---------------------|------------------------|----------|
| Shri C M Vasudev | (Independent Director) | Chairman |
| Shri S S Yadav | (Managing Director) | Member |
| Shri Sharad Krishna | Director HR | Member |
- The Board of Directors shall have power to nominate more persons to the aforesaid Committee by nominating other members of the Board.
- Managing Director UPCL shall be the permanent member of the CSR Committee.
- CSR Committee being a statutory sub-committee of the Board, therefore, Company Secretary UPCL shall be the Secretary. CSR Committee will conduct the business and keep records as per the provisions of the Companies Act, 2013. Managing Director shall have the full power to co-ordinate the planning, identification of CSR activities, award the work and monitor its progress from time to time subject to the superintendence and control of the CSR Committee.
- After the approval of statutory limit of 2% by the CSR Committee, it will be within the full powers of Managing Director to spend such amount on such schemes and in such areas as have been specified by the CSR Committee.
- Any fund that is left unutilized in any financial year shall be carried forward to the next year as per the provisions of the Companies Act, 2013.

Items that can be undertaken under CSR

All items that are enumerated in Schedule VII of The Companies Act, 2013 as amended up to date can be undertaken by the Company under the CSR Policy. The updated list of the activities on the date of formation of this policy is enclosed with this policy and shall form an essential part of this policy. Out of the aforesaid list, the Company will prepare a list of CSR Projects/Programmes which the Company plans to undertake during the implementation year by specifying modalities of execution in the areas/sector chosen and implementation schedule for the same.

Methodology and other Covenants

- I. The Board of Directors shall ensure that the Company spends in a financial year at least 2% of the average net profit of the Company made in immediately preceding three financial years in pursuance of the Corporate Social Responsibility activities and preference will be given to local area and areas around the Company where it operates for spending this amount.
- II. The Corporate Social Responsibility activities shall be undertaken by the Company as a project or programme or activities (either new or ongoing) excluding the activities undertaken by the Company in pursuance of normal course of the business.
- III. The Company may decide to undertake the Corporate Social Responsibility activities either through registered trust or registered society or Section 8 Company under the Companies Act, 2013.
- IV. The CSR Committee shall be specifying the modalities of utilization of funds on such projects and programmes and its monitoring and reporting mechanism also. Managing Director will have full powers to implement the policy.
- V. Subject to prior approval of CSR Committee, the Company may also collaborate with other Companies for undertaking projects or programmes of Corporate Social Responsibility activities in such a manner that the Corporate Social Responsibility Committees of the respective Companies are in a position to report separately on such projects or programmes.
- VI. The trust, society and Section 8 Company as referred under Clause (iii) and (v) shall have at least 2 years experience of the related social development activities.
- VII. Any activity undertaken outside India shall not be treated as expenditure under Corporate Social Responsibility Policy.

- VIII. The programmes or activities that benefit only the employees of the Company and their families shall not be considered as Corporate Social Responsibility activities.
- IX. The Company can spend CSR funds on an activity which is listed under Schedule VII but is for the development of personnel of its own or the implementing agency. Provided that such expenditure incurred shall not exceed 5% of Corporate Social Responsibility expenditure for that financial year and the modalities of such development will require prior approval of CSR Committee.
- X. Any contribution made directly or indirectly to any political parties shall not be considered as Corporate Social Responsibility activities.
- XI. For Corporate Social Responsibility activities separate corpus shall be maintained and any surplus/un-utilized amount arising out of this activity shall not form a part of the business of the Company and shall be carried forward.
- XII. As per Section 134(3) (o) of the Companies Act 2013 the details of Corporate Social Responsibility in the prescribed form shall be incorporated in the Report of Board of Directors' to the Shareholders and the reasons of unspent amount, if any, shall be explained in such report.

Control, Amendment and Repeal

The implementation, additions, alterations and interpretation of CSR policy shall fall in the ambit and domain of CSR Committee which shall be the final authority in these matters. All major amendments or repeal of the policy shall require approval from the Board.

SCHEDULE VII OF THE COMPANIES ACT, 2013 REGARDING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The following items can be undertaken under Corporate Social Responsibility:-

- (i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation including contribution to the Swachh Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;
- (ii) promoting education, including special education and employment, enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects;

- (iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;
- (iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro-forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund setup by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;
- (v) protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional arts and handicrafts;
- (vi) measures for the benefit of armed force veterans, war widows and their dependents;
- (vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, Paralympics sports and Olympic sports;'
- (viii) contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;'
- (ix) contributions or funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by the Central Government;
- (x) rural development projects.